

I. उत्पादन

2011-12 के दौरान भारत की वृद्धि पर असर डालने वाले घरेलू तथा वैश्विक दोनों कारकों का समाधान न होने के कारण 2012-13 की पहली तिमाही में वृद्धि दर धीमी रही। संकेतकों से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक गतिविधियों में कमी आने एवं सेवा क्षेत्र का कार्यनिष्पादन उचित स्तर से कम रहने के कारण 2012-13 की दूसरी तिमाही में गिरावट जारी रही। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपरंपरागत उपाय करते हुए मौद्रिक सहजता की नीति को अपनाने के बावजूद, वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं पिछली तिमाही से कमजोर हुईं और इसका भारत की भावी वृद्धि की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा। परंतु, हाल में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों से घरेलू बाधाएं कम होने के कारण गिरावट के थमने की संभावना है, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। वृद्धि के पुनरुत्थान के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने की जरूरत है।

वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं पिछली तिमाही की तुलना में कमजोर हुईं

1.1 सरकारी ऋण संकट की आसन्न स्थिति, राजकोषीय समायोजन, बैंकिंग की कमजोरियों एवं विशेष रूप से यूरो क्षेत्र की वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं के कारण वृद्धि के प्रभावित होने चलते वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं और कमजोर पड़ गईं। अमरीका, जापान और चीन में 2012 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर में क्रमशः गिरावट आई जबकि यूरो क्षेत्र एवं यूके सकारात्मक वृद्धि दर हासिल करने में असफल रहे। अमरीकी आवास बाजार में बेहतरी के हल्के संकेत दिखाई देने पर भी फेडरल रिजर्व द्वारा घोषित ओपन-इंडेड मात्रात्मक सहजता के बावजूद अमरीका में फिस्कल क्लिफ के लागू होने की संभावना अमरीका और वैश्विक बहाली के लिए काफी जोखिम पैदा करती है। फिस्कल क्लिफ का तात्पर्य 2012 और 2013 के बीच फेडरल बजट के घाटे में संभावित बड़ी कटौती से है जो जनवरी 2013 से कतिपय करों की दरों में बढ़ोतरी किए जाने और खर्चों में कटौती के चलते जरूरी हो जाएगी।

1.2 आईएमएफ द्वारा इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित वैश्विक आर्थिकपरिदृश्य (डब्ल्यूईओ) में उसने वर्ष 2012 के अपने पूर्वानुमान में वैश्विक वृद्धि के पूर्वानुमान को जुलाई 2012 के 3.5 प्रतिशत से घटाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया। यह मुख्यतः जुलाई 2012 में ईडीई की वृद्धि संबंधी पूर्वानुमान को 5.6 प्रतिशत से कम करके 5.3 प्रतिशत किए जाने के कारण था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि संबंधी पूर्वानुमान 0.1 प्रतिशत अंक कम करके 1.3 प्रतिशत किया गया। 2012 के वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान का नवीनतम संशोधन अप्रैल

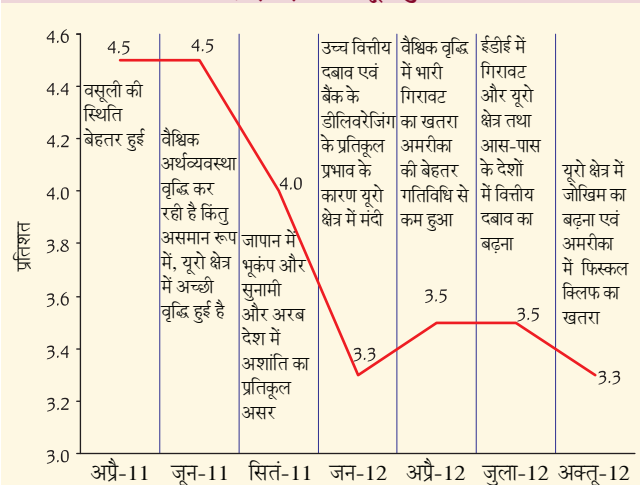
2011 से, अर्थात् जब से वैश्विक बहाली ने जोर पकड़ा, 1.2 प्रतिशत अंक की गिरावट को दर्शाता है (चार्ट 1.1)।

1.3 अमरीकी अर्थव्यवस्था ने 2012 की तीसरी तिमाही में 2.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जो 2012 की पहली तिमाही के 1.3 प्रतिशत की दर से अधिक थी। यूरो क्षेत्र का उत्पादन दूसरी तिमाही में 0.7 प्रतिशत (वार्षिकीकृत) की दर से संकुचित हुआ। विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में भी रोजगार का परिदृश्य धुंधला रहा। तथापि अमरीका में बेरोजगारी दर अगस्त 2012 के 8.1 प्रतिशत से घटकर सितम्बर 2012 में 7.8 प्रतिशत रह गया।

1.4 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संकट एवं घरेलू बाध्यताओं का असर ईडीई की आर्थिक गतिविधि पर भी पड़ा। ब्रिक्स में गिरावट जारी रही। चीन की वृद्धि लगातार सात तिमाहियों में घटकर 2012 की तीसरी तिमाही में 7.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही। रूस की वृद्धि दर 2012 की दूसरी तिमाही में और घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई जो लगातार तीन तिमाहियों से निरंतर घट रही है। ब्राजील की वृद्धि दर लगातार दस तिमाहियों में घटकर 0.5 प्रतिशत तक आ गई। दक्षिण अफ्रीका की वृद्धि दर में मामूली सुधार हुआ लेकिन पिछली चार तिमाहियों में वृद्धि दर 3.0 प्रतिशत से कम रही। वैश्विक वृद्धि और व्यापार में जोखिम के चलते उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की संभावनाओं में निकट भविष्य में सुधार के आसार नहीं दिखाई देते।

1.5 वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में अगस्त 2012 में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो नवम्बर 2009 की शून्य वृद्धि के बाद अब तक की

चार्ट 1.1: 2012 में वैश्विक वृद्धि के संबंध में आईएमएफ का पूर्वानुमान



स्रोत: वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक एंड अपडेट्स (विभिन्न अंक)

सबसे धीमी गति है (चार्ट I.2)। अग्रणी संकेतक जैसे कि खरीदकर्ता प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) तीसरी तिमाही में कोई खास सुधार नहीं दर्शाता। वैश्विक व्यापार के आकार में जुलाई 2012 में गिरावट आई (चार्ट 1.3)। वैश्विक गतिविधि और भारत के बीच आपसी संबंधों को देखते हुए, वैश्विक औद्योगिक गतिविधि और व्यापार में आई गिरावट भारत की वृद्धि संबंधी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

अमरीका के मौजूदा फिस्कल क्लिफ से होने वाला जोखिम अहम बना हुआ है

1.6 अमरीका के फिस्कल क्लिफ से वैश्विक वृद्धि में गिरावट लाने वाला एक बड़ा जोखिम उभर रहा है। अमरीकी कांग्रेस के बजट कार्यालय का पूर्वानुमान है कि अमरीका का राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत अंक घटकर 2013 में जीडीपी का 4 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार तेजी से किए गए राजकोषीय समेकन का वैश्विक वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है (सारणी 1.1)। अमरीका के फिस्कल क्लिफ का भारत की वृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि वैश्विक वृद्धि में भारी गिरावट आती है तो इसका बुरा असर चालू खाते पर भी पड़ेगा, यद्यपि वैश्विक पण्यों की कीमतों में गिरावट आने पर स्थिति कुछ हद तक संभल सकती है।

2012-13 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि धीमी रही

1.7 2012-13 की पहली तिमाही में वृद्धि 5.5 प्रतिशत रही जो पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ी अधिक है लेकिन यह वृद्धि 2011-12 की इसी तिमाही के 8.0 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। सभी तीनों प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, विशेषकर औद्योगिक और

सारणी 1.1: अमरीका के 'फिस्कल क्लिफ' का वैश्विक प्रभाव

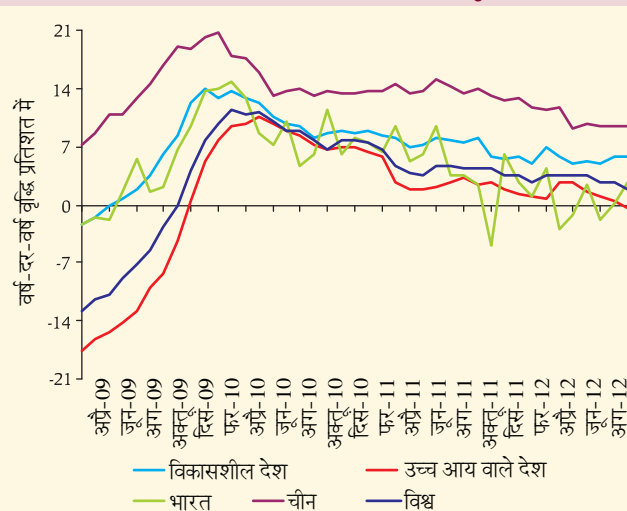
1	बेसलाइन से प्रतिशत अंक परिवर्तन		
	जीडीपी	चालू खाता शेष*	राजकोषीय शेष*
2	3	4	
विश्व	-1.0	-	0.4
अमरीका	-2.2	1.2	2.9
उच्च आय वाले देश	-1.1	0.1	0.8
यूरो क्षेत्र	-0.4	-0.3	-0.1
विकासशील देश	-0.6	-0.4	-0.3
दक्षिणी एशिया	-0.2	0.1	0.1

स्रोत: विश्व बैंक का अनुमान
* जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

सेवा क्षेत्रों में (सारणी 1.2)। विनिर्माण क्षेत्र में खासकर भारी गिरावट आई। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि होने के बावजूद 'व्यापार, होटल, यातायात, भंडारण और संचार' की वृद्धि दर में भारी गिरावट होने के अनुरूप सेवा क्षेत्र की वृद्धि में लगातार दो तिमाहियों में कमी आई।

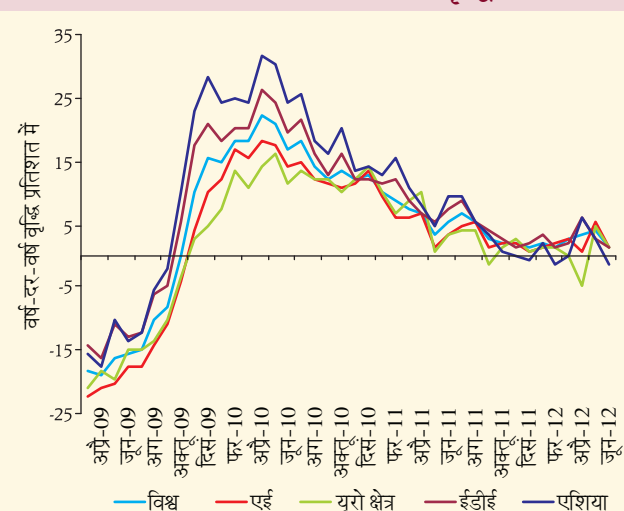
1.8 सितम्बर 2012 के दूसरे सप्ताह से सरकार ने राजकोषीय समेकन के लिए कई नीतिगत उपायों की घोषणा की जिनमें ऊर्जा सब्सिडी को कम करना और पब्लिक उद्यमों की हिस्सेदारी को बेचना शामिल हैं। सरकार द्वारा कई अन्य सुधारात्मक उपाय भी किए गए हैं (सुधारात्मक उपायों के संबंध में सारणी VII.1 देखें)। जहां इन उपायों ने भावनाओं में सुधार लाने में मदद की है, वहीं वृद्धि पर इनका प्रभाव कुछ अंतराल के बाद महसूस किया जाएगा, खासकर एफडीआई और मूलभूत संरचना संबंधी पहलों पर वास्तविक कार्यान्वयन के बाद।

चार्ट I.2: औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि



स्रोत: विश्व बैंक

चार्ट I.3: निर्यात की मात्रा में वृद्धि



स्रोत: सीपीबी वर्ल्ड ट्रेड मॉनीटर

सारणी I.2: जीडीपी की क्षेत्र-वार वृद्धि दर (2004-05 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

मद	2010-11*	2011-12#	2011-12				2012-13
			ति1	ति2	ति3	ति4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.0	2.8	3.7	3.1	2.8	1.7	2.9
2. उद्योग	6.8	2.6	6.5	2.7	0.9	0.7	0.8
2.1 खनन एवं उत्खनन	5.0	-0.9	-0.2	-5.4	-2.8	4.3	0.1
2.2 विनिर्माण	7.6	2.5	7.3	2.9	0.6	-0.3	0.2
2.3 बिजली, गैस और जलापूर्ति	3.0	7.9	7.9	9.8	9.0	4.9	6.3
3. सेवाएं	9.2	8.5	9.3	8.5	8.7	7.5	7.4
3.1 व्यापार, होटल, परिवहन, भंडार और संचार इत्यादि	11.1	9.9	13.8	9.5	10.0	7.0	4.0
3.2 वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	10.4	9.6	9.4	9.9	9.1	10.0	10.8
3.3 सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	4.5	5.8	3.2	6.1	6.4	7.1	7.9
3.4 निर्माण	8.0	5.3	3.5	6.3	6.6	4.8	10.9
4. कारक लागत पर जीडीपी (कुल 1 से 3)	8.4	6.5	8.0	6.7	6.1	5.3	5.5

*: त्वरित अनुमान, # संशोधित अनुमान

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

2012-13 में नकारात्मक उत्पादन अंतर के बने रहने की संभावना

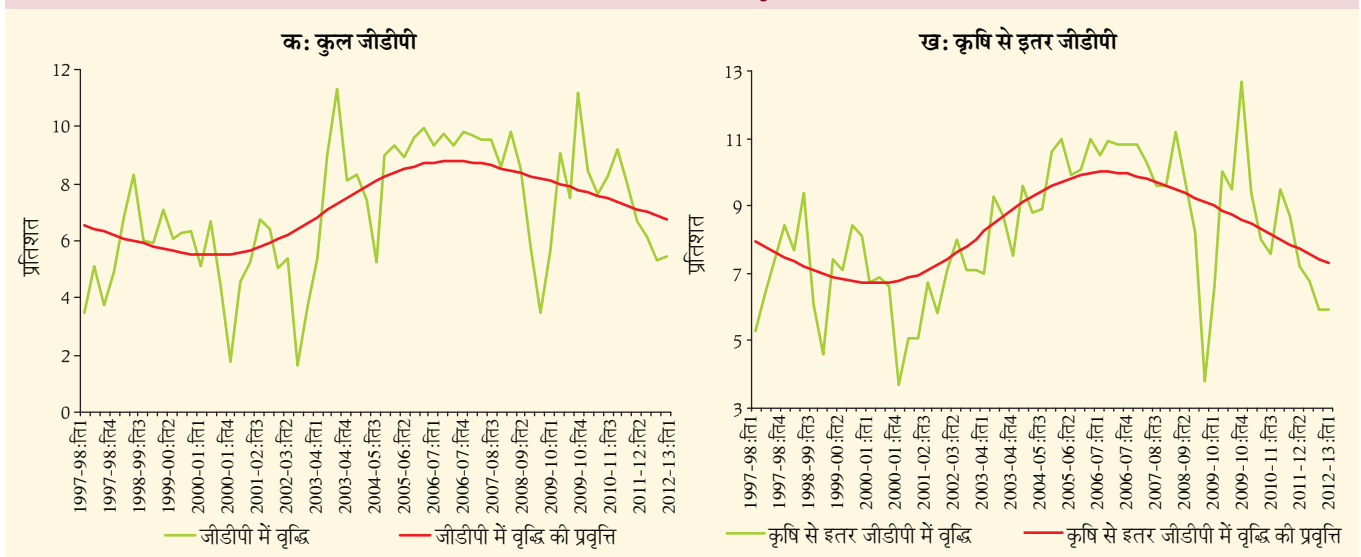
1.9 भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर लगभग 2007-08 के मध्य में सबसे अधिक थी और तब से 2012-13 की पहली तिमाही में उसमें गिरावट जारी रही (चार्ट 1.4)। संभावित उत्पादन के प्राक्कलन के संबंध में कई पद्धति संबंधी मुद्दे हैं और विभिन्न आनुभविक प्राक्कलन काफी अनिश्चितता पैदा करते हैं। फिर भी यह बात स्पष्ट है कि बचत और निवेश में गिरावट, उच्च मुद्रास्फीति और घरेलू संरचनात्मक बाधाओं के साथ-साथ प्रचक्रिय वैश्विक मंदी

के परिणामस्वरूप संभावित उत्पादन घट गया है। वर्तमान अनुमान बताता है कि संभावित वृद्धि दर घटकर लगभग 7.0 प्रतिशत हो गया होगा। उत्पादन अंतर लगातार चार तिमाहियों में नकारात्मक रहा है।

विलंबित और अनियमित मानसून का खरीफ उत्पादन पर असर लेकिन रबी की अच्छी संभावनाएं

1.10 2012 में न केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने में देरी हुई बल्कि उसकी प्रगति और फैलाव असमान था, खासकर जून और जुलाई में जब अवधि में जब खरीफ की फसल की बुआई की जाती है।

चार्ट I.4: जीडीपी वृद्धि

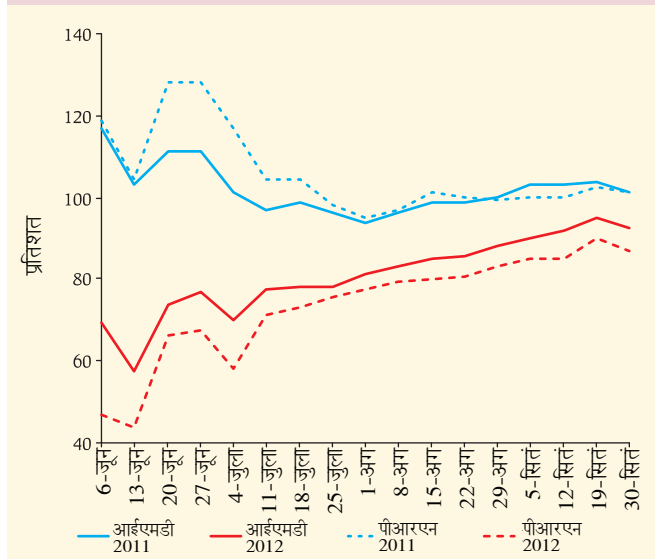


इसके परिणामस्वरूप अधिकांश फसलों की बुआई में देरी हुई। यद्यपि अगस्त और सितम्बर में वर्षा की स्थिति में सुधार हुआ लेकिन पूरे देश में संचयी वर्षा (30 सितम्बर तक) एलपीए से 8 प्रतिशत कम थी। रिजर्व बैंक का उत्पादन-भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन) पूरे मौसम में 13 प्रतिशत की कमी दर्शाता है (चार्ट 1.5)।

1.11 वर्षा में कमी के चलते कई फसलों की बुआई में गिरावट आई जिनमें मुख्यतः मोटे अनाज और दालें शामिल हैं (सारणी 1.3)। प्रथम पूर्वानुमान के अनुसार बुआई में विलंब का, विशेषकर जुलाई 2012 में, खरीफ फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खरीफ मौसम के उत्तरार्ध में मानसून के पुनरुत्थान तथा सूखे जैसी स्थिति से कुछ हद तक निपटने की सरकार की आकस्मिक योजनाओं ने जून और जुलाई 2012 के दौरान मानसून की कमी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहयोग दिया। वर्षा के देरी से, खासकर सितम्बर में आगमन से, मिट्टी में नमी की मात्रा और जलाशय के स्तरों में सुधार हुआ जिससे सर्दी और रबी की फसलों की संभावनाएं बेहतर हुईं जो खरीफ फसलों की हानि की भरपाई करने में सहायक हो सकती हैं।

1.12 चावल और गेहूँ का लगभग 67 मिलियन टन (सितम्बर 2012) का वर्तमान स्टॉक भंडारण के मानदण्डों को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा है (चार्ट 1.6)। तथापि, स्थिर मूल्यों पर खाद्य और पोषण की सुरक्षा चिंता का विषय रहा है क्योंकि मानसून की कमी के चलते खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने का दबाव देखा गया है (विवरण के लिए मूल्य की स्थिति संबंधी अध्याय VI देखें)। कतिपय

चार्ट 1.5: वर्षा सूचकांक



कृषिजन्य पण्यों की भावी कीमतों में, कमजोर मानसून की चिंता के चलते, जून-जुलाई के दौरान उछाल भी देखा गया है।

औद्योगिक वृद्धि के लिए निवेश की बहाली अनिवार्य

1.13 अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारी गिरावट आई। यह मुख्यतः निवेश संबंधी गतिविधि में मंदी के चलते पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन में गिरावट के कारण था (सारणी 1.4)। औद्योगिक उत्पादन में खनन क्षेत्र में गिरावट आने के कारण

सारणी 1.3: खरीफ की बुआई और उत्पादन

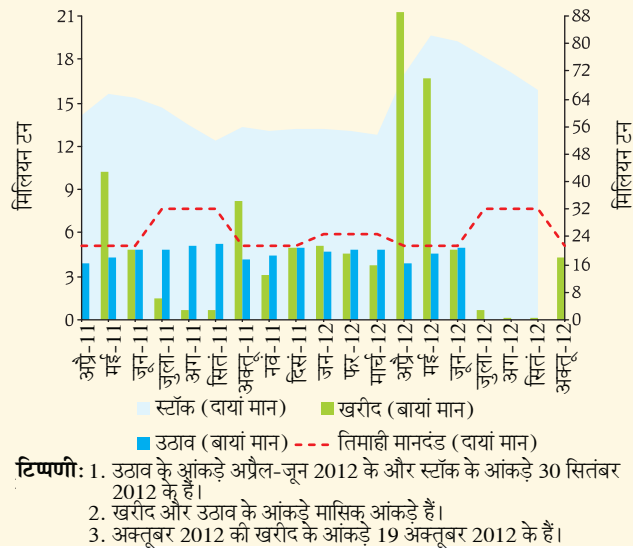
(क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में; उत्पादन मिलियन टन में)

फसल	सामान्य	बुआई*		खरीफ का उत्पादन		2011 की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
		2011	2012	2011 का चौथा पूर्वानुमान	2012 का पहला पूर्वानुमान	बुआई (3) की तुलना में (4)	उत्पादन (5) की तुलना में (6)
1	2	3	4	5	6	7	8
खाद्यान्न	71.9	72.1	66.5	129.9	117.2	-7.8	-9.8
चावल	39.1	40.1	39.2	91.5	85.6	-2.2	-6.4
मोटे अनाज	21.9	20.7	17.8	32.3	26.3	-14.0	-18.6
दाल	11	11.3	9.5	6.2	5.3	-15.9	-14.5
तिलहन	17.9	18.5	17.5	20.8	18.8	-5.4	-9.6
गन्ना	4.7	5.1	5.1	357.7	335.3	0.0	-6.3
कपास #	9.9	12.2	11.6	35.2	33.4	-4.9	-5.1
जूट और मेस्ता ##	0.8	0.8	0.8	11.6	11.3	0.0	-2.6
सभी फसलें	105.2	108.7	101.5	-	-	-6.6	-

*: फसल की पूरी अवधि #170 किलोग्राम का प्रत्येक मिलियन बेल। ##180 किलोग्राम का प्रत्येक मिलियन बेल।

स्रोत: कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट I.6: खाद्य भंडार और इसके निर्धारक तत्व



भी गिरावट आई। पूंजीगत सामग्रियों को छोड़कर समग्र आईआईपी ने अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (चार्ट 1.7)।

1.14 औद्योगिक कार्यकलापों में आई मंदी का सभी क्षेत्रों में असर देखा गया। निवेश संबंधी गतिविधि के कमजोर पड़ने तथा बाह्य मांग में कमी आने के चलते अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन की समग्र वृद्धि दर में गिरावट के पीछे मुख्य कारण विनिर्माण के प्रमुख उप-क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी और एपरैटस, मोटर वाहन, खाद्य उत्पाद एवं वस्त्र में काफी गिरावट आना था। खनन क्षेत्र में विनियामक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के चलते गिरावट जारी रही। कोयला और लौह अयस्क के खनन संबंधी नीतिगत अनिश्चितताएं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए बाधक बन सकती हैं। ऊर्जा उत्पादन में कोयले की आपूर्ति में कमी और असमान मानसून की स्थिति दोनों ही कारणों से अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान भारी गिरावट आई।

1.15 उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर सभी श्रेणियों की वस्तुओं में गिरावट देखी गई। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान गिरावट मुख्यतः निवेश मांग के कमजोर पड़ने के कारण थी। पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर पूंजीगत वस्तुओं की कमी की कुछ हद तक भरपाई की गई। अतएव इस अवधि के दौरान इनके आयातों में काफी बढ़ोतरी हुई।

1.16 अप्रैल 2010 से मार्च 2012 के दौरान विनिर्माण वस्तु उद्योगों के उत्पादन और निर्यात के बीच के संबंध का विश्लेषण इस बात

सारणी I.4 : औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक: उद्योगों का क्षेत्र-वार और उपयोग आधारित वर्गीकरण

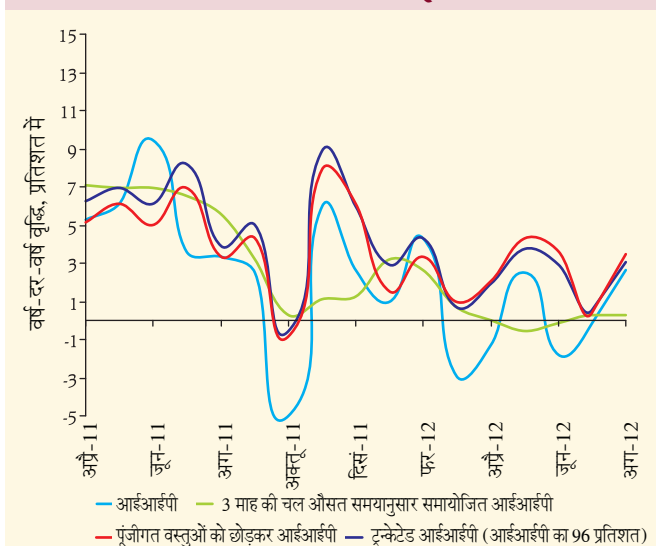
उद्योग समूह	आईआईपी में भारांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		अप्रैल-अगस्त		अक्टूबर 2012
		अप्रैल-मार्च 2011-12	2011	
1	2	3	4	5
क्षेत्र-वार				
खनन	14.2	-2.0	-0.5	-0.6
विनिर्माण	75.5	3.0	6.0	0.0
बिजली	10.3	8.2	9.5	4.8
उपयोग-आधारित				
मूल वस्तुएं	45.7	5.5	7.6	2.8
पूंजीगत वस्तुएं	8.8	-4.0	7.3	-13.8
मध्यवर्ती वस्तुएं	15.7	-0.6	0.8	0.6
उपभोक्ता वस्तुएं (क+ख)	29.8	4.4	4.4	3.5
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8.5	2.6	4.5	5.7
ख) उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	21.3	5.9	4.3	1.6
सामान्य	100	2.9	5.6	0.4

अ: अनतिम

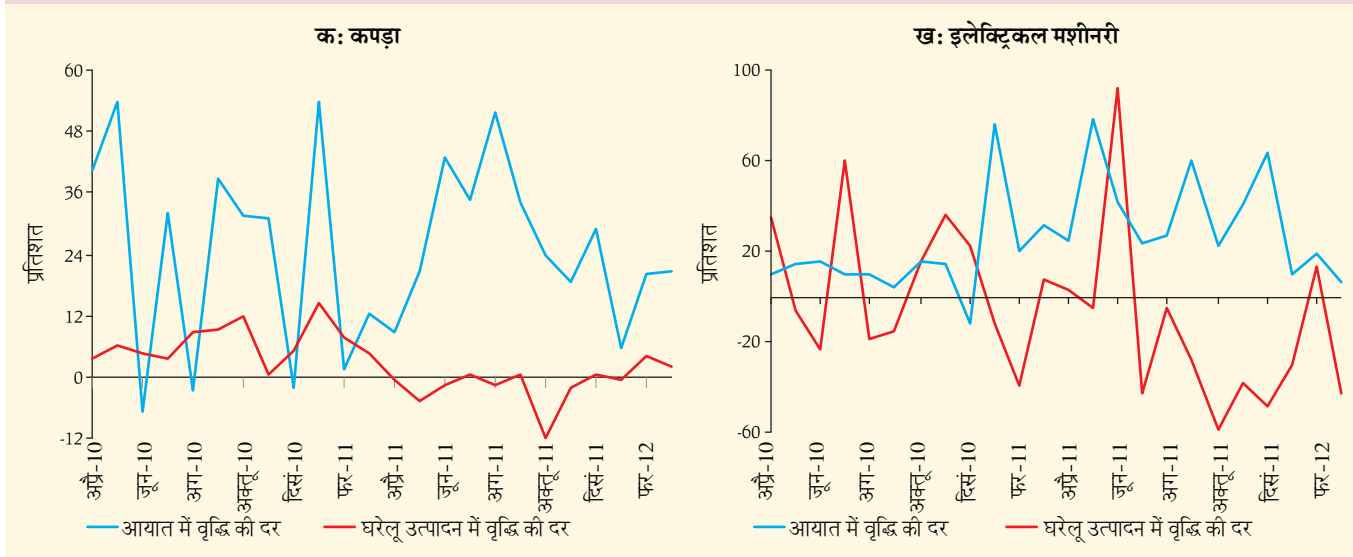
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

की पुष्टि करता है कि वस्त्र और इलेक्ट्रिकल मशीनरी वस्तुओं के मामले में सांख्यिकीय दृष्टि से घरेलू उत्पादन और निर्यातों के बीच आंकड़ों में उल्लेखनीय एवं ऋणात्मक संबंध है। यह ऋणात्मक संबंध सूचित करता है कि वस्त्र और इलेक्ट्रिकल मशीनरी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कमी आई है जिसके चलते घरेलू उत्पादन की कमी को आयातों से पूरा किया गया (चार्ट 1.8)।

चार्ट I.7: औद्योगिक वृद्धि



चार्ट 1.8 : विनिर्मित वस्तुओं के आयात की तुलना में घरेलू उत्पादन



1.17 औद्योगिक वृद्धि को बहाल करने के लिए निवेश में तेजी जाने हेतु शीघ्रता से निर्णय लिये जाने की जरूरत है और यह कार्य खासकर नीतिगत बाधाओं को कम करके और आपूर्ति संबंधी प्रमुख अड़चनों को समाप्त करके किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय निवेश बोर्ड (एनआईबी) स्थापित करने के हाल के प्रस्ताव का उद्देश्य बड़ी परियोजनाओं के संबंध में समन्वय स्थापित करना और निवेश की अनुमति की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करना है ताकि निवेश के माहौल में सुधार लाया जा सके। चूंकि उप-राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में परियोजना संबंधी अनुमति की भी आवश्यकता होती है इसलिए एनआईबी की परिधि में न आने वाली एजेंसियों के साथ-साथ सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया जाना जरूरी है।

1.18 घरेलू औद्योगिक उत्पादन की बहाली वैश्विक वृद्धि की बेहतरी पर भी आश्रित हो सकती है। घरेलू और वैश्विक आईआईपी के बीच मजबूत सह-प्रवृत्ति देखी गई; जिसका सहसंबंध गुणांक अप्रैल 2008 से अगस्त 2012 की अवधि में उच्च अर्थात् 0.7 था (चार्ट 1.2 देखें)।

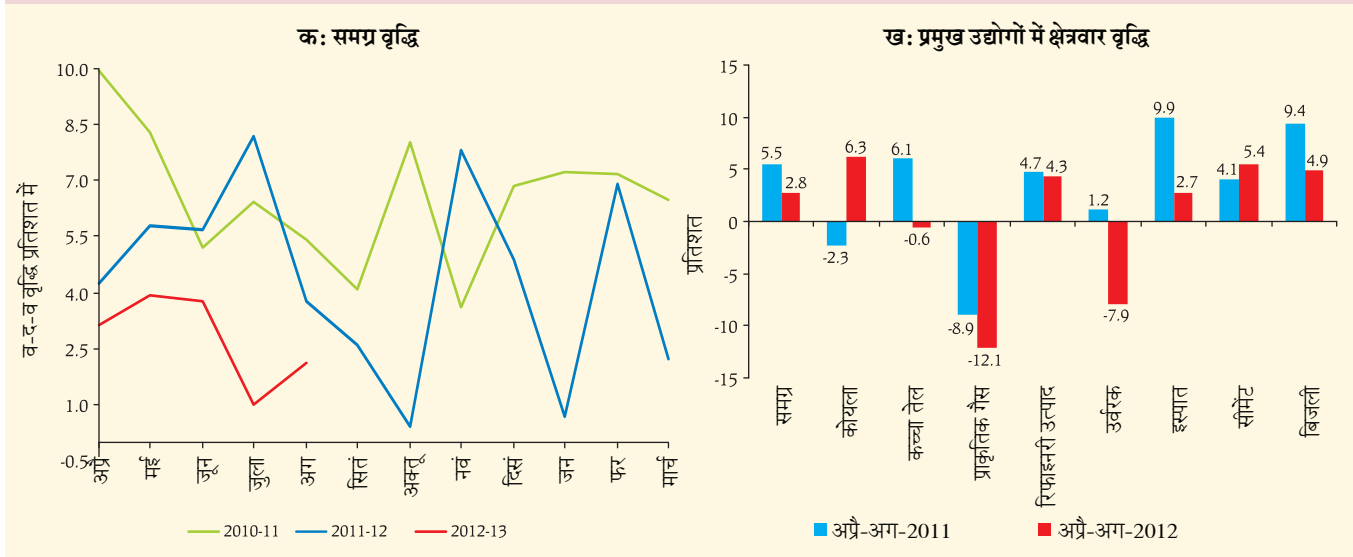
निवेश चक्र की बहाली ऊर्जा और कोयला उद्योग की नीतिगत अनिश्चितताओं के समाधान पर निर्भरशील

1.19 आठ महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनागत उद्योगों की वृद्धि दर अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई जबकि यह वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.5 प्रतिशत थी (चार्ट 1.9)। आगे मंदी से जूझते इन उद्योगों की स्थिति निवेश संबंधी गतिविधि की

बहाली पर निर्भर करेगी। यह स्थिति ऊर्जा और कोयला उद्योगों द्वारा सामना की जा रही नीतिगत अनिश्चितताओं के समाधान पर निर्भर करती है। नए बड़े ऊर्जा उद्योग की उत्पादन क्षमताओं का ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उत्पादन पूर्व चरण पर पहुंचने के बावजूद इन क्षमताओं ने निविष्टि की आपूर्ति संबंधी दबाव के चलते वांछित परिणाम नहीं दिया। यद्यपि 55जीडब्ल्यू से अधिक की नई क्षमता का निर्माण किया गया फिर भी थर्मल पावर में नई क्षमता का बड़ा हिस्सा कोयले की कमी के कारण प्रभावित हुआ। थर्मल पावर के उत्पादन के लिए 2012-13 में 476 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है लेकिन केवल 407 मिलियन टन की आपूर्ति ही देशी स्रोतों से की जा सकती है और बाकी आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर होना होगा। बारहवीं पंच-वर्षीय योजना में इस मांग-आपूर्ति अंतर के और बढ़ने की संभावना है। कोयला लिंकेज के आधार पर शुरू किए गए नए संयंत्रों को प्रतिबद्ध ऊर्जा आपूर्ति करार (एफएसए) के अभाव में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई पावर प्रोजेक्ट की विभिन्न अनुमतियां न मिलने के चलते रुके पड़े हैं। साथ ही, पावर का वितरण वित्तीय दबाव में आ गया है और राज्य पावर वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार ₹1.9 ट्रिलियन का संचित ऋण का भार है। बैंक वित्त का एक बड़ा हिस्सा अशोध्य ऋण के रूप में इन डिस्कॉम के पास फंसा हुआ है।

1.20 तथापि, इस क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों की समाधान करने की दिशा में गत दो महीनों में पर्याप्त प्रगति की गई है। नया एफएसए, जिसमें आश्वस्त कोयला गुणवत्ता (एसीक्यू) के 80

चार्ट 1.9: प्रमुख उद्योगों में वृद्धि दर



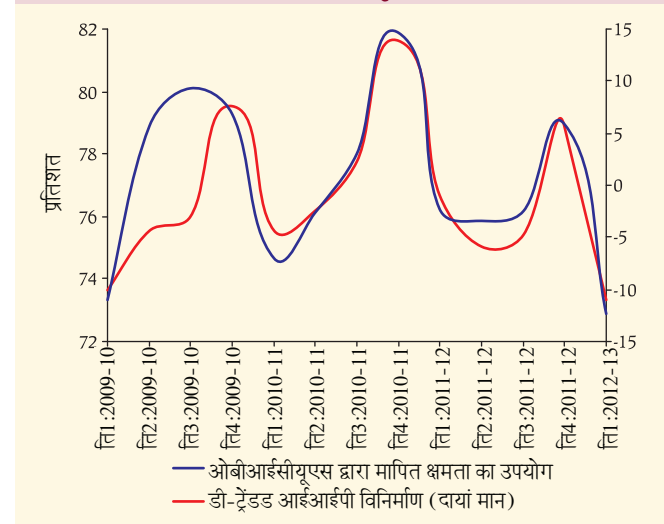
प्रतिशत के पूर्व-स्वीकृत डिसइन्सेंटिव ट्रिगर पर पर्याप्त ग्रेडेड पेनल्टी क्लॉजेस शामिल हैं, अब कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा अनुमोदित है और संभावना है कि शीघ्र इस पर ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। डिस्कॉम के वित्तीय पुनर्गठन की योजना बनाई गई है जिसका लक्ष्य डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में बदलाव लाना है (पैरा 11.16 देखें)। तथापि, कोयला आपूर्ति के मुद्दे का व्यापक समाधान, आपूर्ति संबंधी कमियों को इस बीच आयात के जरिए पूरा करने के साथ-साथ उपयुक्त कीमत निर्धारण या प्रभावी वैकल्पिक प्रणाली पर निर्भर करता है। साथ ही कोयला ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहने की जरूरत है ताकि यह मुद्दा बारहवीं पंच-वर्षीय योजना के बाद तक न टलता रहे। अतः वर्तमान उपाय सही दिशा की ओर उठाए गए कदम हैं इसलिए बुनियादी संरचना क्षेत्र में निवेश चक्र को पुनः गति प्रदान करने के लिए शेष मुद्दों का तेजी से समाधान किए जाने की जरूरत है।

1.21 हाल की अवधि में लिए गए अन्य निर्णय, जैसे सरकारी भूमि के स्वत्वधिकार के अंतरण की अनुमति देकर कतिपय श्रेणी के प्रोजेक्टों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाना, 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि के संबंध में अनुमति क्षेत्रीय स्तर पर दिया जाना, नीतिगत अनिश्चितताओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह निर्णय लिया गया है कि वन और पर्यावरण संबंधी अनुमति की प्रोसेसिंग एक साथ की जाएगी ताकि विलंब से बचा जा सके। साथ ही, हाल की नीतिगत पहलें जैसे खुदरा व्यापार, सिविल एविएशन और पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजों में एफडीआई की अनुमति दिया जाना तथा डीजल की कीमतों को युक्तिसंगत बनाना, निवेश के वातावरण में सुधार लाएंगी।

क्षमता उपयोग तेरह तिमाहियों में सबसे निम्नतम स्तर पर रहा

1.22 आर्थिक वृद्धि में गिरावट के चलते रिजर्व बैंक के 18वें दौर के आदेश बही, माल सूची एवं क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के अनुसार क्षमता उपयोग का स्तर 2012-13 की पहली तिमाही में तीन साल के निम्नतम स्तर पर रहा (<http://www.rbi.org.in/OBICUS18>)। क्षमता उपयोग और डी-ट्रेंडेड आईआईपी विनिर्माण के बीच दृढ़ उतार-चढ़ाव देखा गया है (चार्ट 1.10)। सर्वेक्षण से आगे पता चलता है कि नए आदेशों में तिमाही-दर-तिमाही और वर्ष-दर-वर्ष दोनों दृष्टियों से उच्चतर वृद्धि

चार्ट 1.10 : क्षमता का उपयोग और औद्योगिक वृद्धि



सारणी 1.5 : सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के संकेतक

(वृद्धि प्रतिशत में)

सेवा क्षेत्र के संकेतक	2010-11	2011-12	अप्रै-सित 2011-12	अप्रै-सित 2012-13
1	2	3	4	5
पर्यटकों का आगमन	9.5	8.6	9.3	3.4
सीमेंट	4.5	6.7	4.1#	5.4#
इस्पात	13.2	7.0	9.9#	2.7#
सेल फोन कनेक्शन (मिलियन में) \$	227.3	107.6	46.8*	-5.7*
ऑटोमोबाइल बिक्री	16.8	11.2	12.0	3.6
रेलवे राजस्व अर्जक माल परिवहन	3.8	5.2	4.8	4.8
प्रमुख बंदरगाहों पर डोया गया माल (कार्गो)	1.6	-1.7	3.1	-3.3
नागर उड्डयन				
देशी माल भाड़ा	23.8	-4.8	-5.1*	3.8*
अंतरराष्ट्रीय माल भाड़ा	17.7	-1.9	3.9*	-4.3*
विदेशी यात्रियों की आवाजाही	10.3	7.6	8.8*	3.3*
देशी यात्रियों की आवाजाही	18.1	15.1	18.0*	-0.5*

#: आंकड़े अप्रैल-अगस्त के हैं।

*: आंकड़े अप्रैल-जुलाई 2012 के हैं।

\$: आंकड़े वायरलेस ग्राहकों में हुई वृद्धि के हैं।

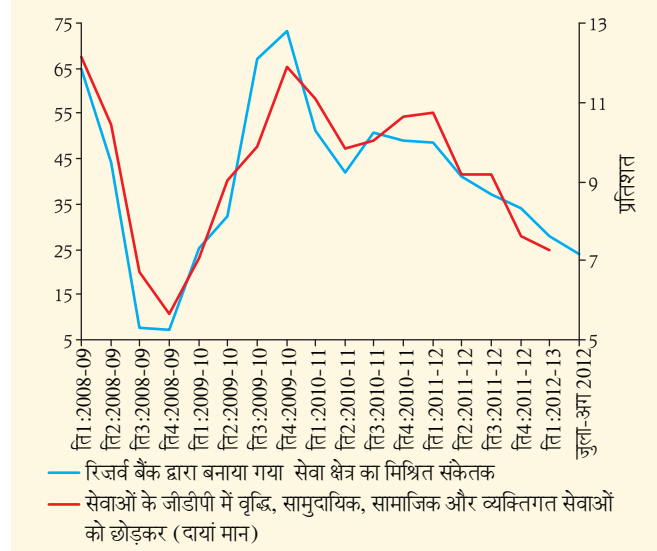
स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, एसआईएम और सीएमआईई।

हुई, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होने के पीछे आंशिक कारण निम्नतर आधार था। नए आदेशों को पूरी तरह पूरा करने में अक्षमता के चलते लंबित आदेशों में इजाफा हुआ।

सेवा क्षेत्र के प्रमुख संकेतक मंदी का संकेत देते हैं

1.23 2012-13 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रही जो तेरह तिमाहियों में निम्नतम है। इसका मुख्य कारण व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र का खराब प्रदर्शन था। औद्योगिक क्षेत्र के संकुचित होने और कमजोर मांग के चलते सेवा क्षेत्र की वृद्धि में बाधा आई। सेवा क्षेत्र के प्रमुख संकेतक वृद्धि दर

चार्ट 1.11 : सेवा क्षेत्र का समेकित संकेतक



में आगे और गिरावट आने का संकेत देते हैं (सारणी 1.5)। रिज़र्व बैंक के सेवा क्षेत्र समेकित संकेतक द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है (चार्ट 1.11)।

हाल की सुधारात्मक पहल स्थिति में बदलाव लाने में सहयोग दे सकती है।

1.24 भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारकों में घरेलू के साथ-साथ बाह्य दोनों शामिल हैं। प्रमुख घरेलू कारक जो वृद्धि के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, वह है नीतिगत अनिश्चितताएं और सुधार की कमी। सितम्बर 2012 से अनेक सुधार योजनाओं की घोषणा की गई जिससे निवेश का वातावरण बेहतर होना चाहिए और घरेलू एवं विदेशी दोनों निवेशों को बढ़ावा मिलना चाहिए। बहाली सुनिश्चित करने के लिए इन सुधार उपायों की घोषणा करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसका लाभ तभी मिल सकेगा जब इसका सफल कार्यान्वयन भी हो।